



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4067]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 18, 2019/अग्रहायण 27, 1941

No. 4067]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 18, 2019/AGRAHAYANA 27, 1941

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 दिसम्बर 2019

**का.आ. 4526(अ).—** केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना अपेक्षित है कि रक्षा स्थापनों में उद्योग में लगी ऐसी सेवाएं, जो औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की पहली अनुसूची की मद 8 के अधीन आती हैं, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए लोक उपयोगी सेवा होगी;

और केन्द्रीय सरकार अंत में यह घोषित करती है कि उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उक्त उद्योग ऐसी लोक उपयोगी सेवा होगी, जिसे भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ.1959(अ), तारीख 13 जून, 2019 द्वारा 22 जून, 2019 से छह मास की अवधि के लिए अधिसूचित किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में उक्त उद्योग के लोक उपयोगी सेवा की प्राप्ति की अवधि का छह मास की अवधि के लिए बढ़ाया जाना अपेक्षित है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 2 के खंड (द) के उपखंड (vi) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा स्थापनों से लगी सेवाओं को 22 दिसंबर, 2019 से छह मास की अवधि के लिए उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है।

[फा. सं. एस.11017/8/2011-आईआर (पीएल)]

कल्पना राजसिंहोत, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th December, 2019

**S.O. 4526(E).—** Whereas the Central Government is satisfied that the public interest so requires that the services engaged in the industry of defence establishments, which is covered under item 8 of the First Schedule to the Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947), to be a public utility service for the purpose of the said Act;

And whereas the Central Government has lastly declared the said industry to be public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months from the 22<sup>nd</sup> June, 2019 *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment number S.O. 1959 (E), dated 13<sup>th</sup> June, 2019;

And whereas the Central Government is of the opinion that public interest requires the extension of the public utility service status to the said industry for a further period of six months;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares the services engaged in the industry of defence establishments to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months with effect from the 22<sup>nd</sup> December, 2019.

[F. No. S-11017/8 /2011-IR (PL)]  
KALPANA RAJSINGHOT, Jt. Secy.